दक्षिण रेलवे/**SOUTHERN RAILWAY**

NO.P(PC)524/VII - CPC/Allowances

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 28 -02-2018

आर बी ई सं/**RBE No. 208 / 2017** पी बी सी सं/ **PBC No.28 / 2018**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,

(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Grant of Extra Work Allowance (abolition of existing Rajbasha Allowance)

*****

A copy of Railway Board letter No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl.-5 dt. 02-01-2018 (RBE No.208 / 2017) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 30-04-2010 has been circulated as PBC No. 70 / 2010.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
For Principal Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 87

RBE No. 208/2017

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-5 New Delhi, dated 02.01.2018.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Grant of Extra Work Allowance (abolition of existing Rajbhasha Allowance).

Ref: (i) Board's letter No. E(P&A)I-2009/SP-1/Genl/1 dated 30.04.2010 (Annex-A-9).
(ii) Ministry of Finance's OM No. 13-3/2016-E.III(A) dated 20.07.2017.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to abolish Rajbhasha Allowance (payable as a Special Allowance to Sr. Scale, J.A. Grade and S.A. Grade Officers entrusted with the administrative control of Hindi works) as a separate allowance. The eligible employees will now be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance", which shall be governed as under:

a. Extra Work Allowance will be paid at a uniform rate of 2% (two percent) of the basic pay per month.
b. An employee shall receive this allowance for a maximum period of one year, and there should be minimum gap of one year before the same employee is deployed for similar duties again.
c. This allowance shall not be combined i.e. if the same employee is performing two or more such duties and is eligible for 2% (two percent) allowance for each add-on, then the total Extra Work Allowance payable will remain capped at 2% (two percent) of basic pay.

2. These orders shall be effective from 1st July, 2017.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

Anil Kumar

(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 87
आरबीई नं. 208/2017

सं. ई(पीएंडए)I-2017/एसपी-1/जनरल-5 नई दिल्ली, दिनांक 02.01.2018

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान करना (मौजूदा राजभाषा भत्ता समाप्त करना)।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 30.04.2010 का पत्र सं. ई(पीएंडए)I-2009/एसपी-1/जनरल/1 (अनुलग्नक-ए-9)
(ii) वित्त मंत्रालय का दिनांक 20.07.2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 13-3/2016-ई.III(ए)

******

भत्तों के संशोधन से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति राजभाषा भत्ते (वरिष्ठ वेतनमान, जे.ए. ग्रेड और एस.ए. ग्रेड अधिकारियों, जिन्हें हिंदी कार्यों का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा जाता है, को विशेष भत्ते के रूप में देय) को एक अलग भत्ते के रूप में सहर्ष समाप्त करते हैं। पात्र कर्मचारियों के लिए अब से नया प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू होगा, जो निम्नानुसार लागू होगा:

क. अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान, प्रति माह मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) की एकसमान दर से किया जाएगा।

ख. कर्मचारी को यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और उसी कर्मचारी को पुन: उसी प्रकार के कार्यों के लिए तैनात किए जाने से पूर्व न्यूनतम एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए।

ग. इस भत्ते को जोड़ा नहीं जाएगा अर्थात् यदि एक ही कर्मचारी दो या अधिक ऐसी ड्यूटियों का निष्पादन करता है और ऐसी प्रत्येक ड्यूटी हेतु 2% (दो प्रतिशत) भत्ते के लिए पात्र है, तो कुल देय अतिरिक्त कार्य भत्ता मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) तक ही सीमित रहेगा।

2. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।

अनिल कुमार
(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पीएंडए)-I
रेलवे बोर्ड